

भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था के उत्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय भूमिका (उ० प्र० के जनपद फिरोजाबाद के विशेष संदर्भ में)

रिया यादव

(शोध छात्रा- अर्थशास्त्र) जे० एस० विश्वविद्यालय; शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

Abstract

क्षे. ग्रामीण बैंकों की नीतियों का भारतीय कृषि- अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न योजनानर्गत निर्बल वर्गीय परिवारों को कृषिक तथा सहायक क्रियाकलापों में अतिरिक्त रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के लिए लाभांश, अनुदान तथा ऋण किस्तों के रूप में प्रदान किए गए हैं जिनके सन्दर्भ में विस्तृत विवेचन विगत अध्यायों में दिए गए हैं। जिनमें कृषिक विकास के लिए कृषि उपकरण, निःशुल्क बोरिंग, डीजल इंजन, पम्पसेट, हैरो, ग्रेसर आदि के लिए लाभांश प्रदान किये गए है। सहायक क्रियाकलापों के लिए यथा- बीज, खादों के अतिरिक्त दुधारु भैंस, बैलजोड़ी, भैंसा बुग्गी, सूअर पालन, तेलधानी, चर्म उद्योग, कुम्हार उद्योग, आलू चिप्स उद्योग, पापड़ बनाना, दर्जीगीरी, बढ़ईगीरी, आटा चक्की, मसाला व परचूनी की दुकान, जनरल स्टोर, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, आदि हेतु अनुदानित ऋण प्रदान किए गए हैं। जो कि लाभप्रद सिद्ध हुए हैं।

पारिभाषिक शब्दावली: ग्रामीण बैंक, कृषि-अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

शोध पद्धति : शोध की प्रकृति एवं अध्ययन के उद्देश्यों की दृष्टि से वर्णनात्मक शोध अभिकल्प को चुना गया है। उद्देश्य पूर्ति हेतु 50 निदर्शितों का चयन फिरोजाबाद जनपद (उ० प्र०) से किया गया है।

उद्देश्य:

- (1) क्षे. ग्रा. बैंकों से प्राप्त ऋण से होन वाले आर्थिक विकास के प्रति लाभार्थियों के दृष्टिकोणों का अध्ययन करना।

- (2) प्रति परिवार तथा प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना।
- (3) ग्रामीण निर्बल वर्गों के आर्थिक विकास में क्षे. ग्रा. बैंकों की भूमिका का मूल्यांकन करना।

परिकल्पनायें:

- (1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय प्रणाली सहज तथा सरल है।
- (2) विकास योजनाओं के अन्तर्गत कृषि-अर्थव्यवस्था के उत्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहायक हैं।
- (3) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अहम भूमिका का निर्वाह कर रही है।

अध्ययन की सीमायें :

प्रस्तुत शोध अध्ययन की सम्भावित सीमायें निम्नवत् हैं -

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन 30 प्र0 के जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचल तक ही सीमित है।
2. शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष पूर्ण रूपेण सर्वेक्षित तथ्यों पर आधारित होंगे।

विश्लेषण: ग्रामीण स्तरों पर ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता इसलिये अनुभव की गई क्योंकि सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक (व्यावसायिक) बैंकों जैसी ऋण एजेन्सियाँ ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कई प्रकार की अनुदान राशियाँ प्रदान कर रही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय भूमिका के प्रति निदर्शितों के प्रत्युत्तर निम्नवत् हैं - (सूचनादाताओं से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का विवरण)

1. “क्या क्षे.ग्रा. बैंकों से लाभान्वित होने से कृषि भू-विन्यास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है?”

क्र०	प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	हाँ	48	96.00
2	नहीं	00	00.00
3	उदासीन	02	04.00
		50	100.00

2 “क्या क्षे.ग्रा. बैंकों से लाभान्वित होने से कृषि तकनीक विकसित हुई है ?”

क्र०	प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	हाँ	45	90.00
2	नहीं	01	02.00
3	उदासीन	04	08.00
		50	100.00

“क्या क्षे.ग्रा. बैंकों से लाभान्वित होने से अतिरिक्त रोजगारों के साधन सृजित हुए हैं ?”

क्र०	प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	हाँ	47	94.00
2	नहीं	02	04.00
3	उदासीन	01	02.00
		50	100.00

उपरोक्त तालिका 1,2 एवं 3 के प्राथमिक तथ्यों से स्पष्ट है कि-क्षे.ग्रा. बैंकों से लाभान्वित होने से कृषि भू-विन्यास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, कृषि तकनीक विकसित हुई है एवं अतिरिक्त रोजगारों के साधन सृजित हुए हैं।

4. “क्या अतिरिक्त रोजगारों के सृजन हो जाने से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है ?”

क्र०	प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	हाँ	45	90.00
2	नहीं	02	04.00
3	उदासीन	03	06.00
		50	100.00

प्रस्तुत तालिका के विप्लेषण से स्पष्ट है कि क्या क्षे.ग्रा. बैंकों से लाभान्वित होने से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष: विकास के संदर्भ में क्षे.ग्रा. बैंकों से अनुदानित ऋण किस्तों पर लेने के पक्ष में हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मैनपुरी जनपद की क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंकें, निर्बल वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में अहम भूमिका निर्वाह कर रही हैं। ऐसा सभी लाभार्थी सूचनादाताओं ने स्वीकार भी किया है। कि कृषि संरचना में परिवर्तन होने से कृषि तकनीक काफी अधिक वैज्ञानिक हुई है। इन समस्त प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि- “कृषि संरचना में परिवर्तन होने से कृषकों की तकनीक वैज्ञानिक हुई है जिससे कृषि उत्पादन में इजाफा होना स्वाभाविक ही है।” अर्थात् “क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंकों की वित्तीय भूमिका” निर्बल वर्गों के विकास में रचनात्मक भूमिका निभा रही है। अतः परिकल्पनायें सत्य एवं सार्थक हैं।

संदर्भ

- ओझा,बी०एल० (2009) भारत में आर्थिक नियोजन, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली
- .दत्ता पी०सी; भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक समस्याएं, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर (आई०सी०ए०आर०), नई दिल्ली
- द्विवेदी के०डी; (2008) विकास का अर्थ-शास्त्र,बी०एच०यू० वाराणसी ।
- भाटिया,जे.डी. (2011) नियम पुस्तिका (यथा संशोधित और 1. 4.91 से लागू) भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय,ग्रामीण विकास विभाग,नई दिल्ली।
- भाटी,आर.के. (2013) ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की मार्ग-निर्देशिका, लखनऊ ग्राम्य विकास विभाग,(30प्र०) शासन, लखनऊ ।
- भाटिया जे.डी.; आई.आर.डी.पी.- ऐन इवेलुएशन, इण्डियन जर्नल ऑफ रुरल डबलपमेन्ट, “कुरुक्षेत्र” वाल्यूम 28 नं. 13, 2008 पृ.38
- मलयाद्री पी.; सक्सेज आफ रुरल इकोनोमिक डवलपमेंट - मिथ ऑर रियलिटी, एक्सिस प्रकाशन नई दिल्ली; 2005:13